



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रापिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300]

लौह दिल्ली, सोमवार, मई 29, 1989/ज्येष्ठ 8, 1911

No. 300]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 1989/JYAISTHA 8, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

क्रित मंत्रालय

(गोपनीय नियमांग)

अधिसूचनाएँ

लौह दिल्ली, 29 मई, 1989

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 1988 (2 of 1989), the Central Government hereby appoints the 29th day of May, 1989, as the date on which the said Act, shall come into force in the whole of India.

[No. 2/89-F.No. 664/23/89-Opium]

का.आ. 379(अ) :—केन्द्रीय मंत्रालय, स्वास्थ्य और मन: प्रभावी पदार्थ (मंशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 2) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रतल मनिताओं का प्रयोग करते हुए, 1989 को उम तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिसको उक्त अधिनियम समस्त भारत में प्रवृत्त होगा।

[संलग्न 2/89-का.नं 664/23/89-आफोम]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th May, 1989

S.O. No. 380(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, (61 of 1985) the Central Government hereby constitutes a Fund to be called the National Fund for Control of Drug Abuse.

[No. 3/89-F.No. 664/23/89-आफीम]

का.आ. 381(ज) :—केन्द्रीय सरकार, भारत शौषधि और मम: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त जटियों का प्रयोग करते हुए, उनकी परिसंकट-मय प्रकृति, चौरी के लिए बेघना, समुचित खंडालण स्थान के प्रतिक्षापन और प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित स्वाक्षर मालिनियों शांत गत: प्रभावी पदार्थों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:—

1. रक्षापक शौषधियाँ:

- (i) अफीम;
- (ii) आर्फीन;
- (iii) हार्टलैन;
- (iv) गाजा;
- (v) हशीश;
- (vi) कोहीन,
- (vii) थियानीन;
- (viii) कोकेन;
- (ix) पीस्ट तृण, और;
- (x) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (xi) के अधीन या परिचालित कोई अन्य विनिमित शौषधि।

2. मन:प्रभावी पदार्थः

- (i) मैथा श्वासोन;
- (ii) टी.एच.सी.;
- (iii) एमफेटामिन; और
- (iv) उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड () के xxiii] मधीन या परिचालित कोई अन्य मन: प्रभावी पदार्थ।

[म. 4/89-फा.स० 664/23/89-आर्फीम]

का.आ. 382 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, स्वाक्षर शौषधि और प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 65 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीषे दी गई सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वा, (जो सीमांशुक और उत्पाद शूलक कलक्टर हैं) उक्त अधिनियम के अधीन सक्रम प्राधिकारी के खल्तीयों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती हैं, और निर्देश देती है कि उक्त गवर्नर प्राधिकारी उस सारणी के स्तम्भ 3 में की तत्पात्री प्रयिकियों में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की बाबत खल्तीयों का निर्वहन करें।

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	व्यक्तिगति
(1)	(2)	(3)
1.	श्री एम.एस. कंवल, केन्द्रीय उत्पाद शूलक कलक्टर। सक्रम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय हलाहल होगा।	स्वाक्षर शौषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 65 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति, जो रक्षापक पदार्थ नियंत्रण व्यवो, वाराणसी के क्षेत्रीय एकक की प्राधिकारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितवद्ध है।
2.	श्री के.बी. बेद्यनाथन, सीमांशुक कलक्टर (निवारक), सक्रम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय मुम्बई होगा।	स्वाक्षर शौषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 65 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति, जो रक्षापक पदार्थ नियंत्रण व्यवो, मुम्बई के क्षेत्रीय एकक की प्राधिकारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितवद्ध है।

1	2	3
3.	श्री डॉ. के. आचार्य, भीमाश्रम कलेक्टर (निश्चय), मध्यम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय कलकत्ता होगा।	स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिविष्ट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण व्युत्ति कलकत्ता के खेत्रीय एक की प्रधिकारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से अंजित संपत्ति में भागी तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितमद्दृश हैं।
4.	श्री प. के. पाण्डे, सोमा शुल्क कलेक्टर, राजम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली होगा।	स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिविष्ट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण व्युत्ति, दिल्ली के खेत्रीय एक की प्रधिकारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से अंजित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितमद्दृश हैं।
5.	श्री पर. प. गोविन्दराज, भीमाश्रम कलेक्टर, मध्यम प्राधिकारी जिनका मुख्यालय मद्रास होगा।	स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिविष्ट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण व्युत्ति, मद्रास के खेत्रीय एक की प्रधिकारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से अंजित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितमद्दृश हैं।

[सं. 6189-फा.सं. 664/23/89-प्रक्रम]

S.O. No. 382(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 680 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby authorises the officers specified in column 2 of the Table below (being Collectors of Customs and Central Excise), to perform the functions of the Competent Authority under the said Act and direct that the said Competent Authorities perform the functions in respect of the persons specified in the corresponding entries in column 3 thereof.

TABLE

S. No.	Name of Officers	Jurisdiction
1	2	3
1.	Shri M.S. Kanwal, Collector of Central Excise.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the Zonal unit of Narcotics Control Bureau, Allahabad.

1	2	3
2.	Shri K.V. Vaidya-nathan Collector of Customs(P) Com-petent Authority with Headquarters at Bombay.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Pyschotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the zonal unit of Narcotics Control Bureau, Bombay.
3.	Shri D.K. Acharya, Collector of Cus-toms (Preventive) Competent Autho-rity with Head-quarters at Calcutta.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the zonal unit of the Nar-cotics Control Bureau, Calcutta.

1	2	3	1	2	3
4.	Shri A.K. Pandey, Collector of Cus- toms Competent Authority with Headquarters at New Delhi.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired pro- perty within the jurisdic- tion of the zonal unit of the Narcotics Control Bureau, Delhi.	5. Shri S.A. Govinda- raj, Collector of Customs Compe- tent Authority with Headquarters at Madras	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired prop- erty within the jurisdiction of the zonal unit of the Narcotics Control Bureau, Madras.	
					[No. 5189-F.No. 664/23/89-Opium]

का.मा. 383 (ध्र).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक शौषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 68क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के सम्बन्ध 2 में विनिरिट शक्तिकार्तियों को, (जो भारत सरकार के संयुक्त राजियों की परिंतर से नीचे के अधिकारी नहीं हैं) उक्त अधिनियम के प्रधीन प्रणालक के कुर्यातों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करते हैं, और निवेश देते हैं कि उक्त प्रशासक उस सारणी के सम्बन्ध 3 में की तत्प्राची प्रविधियों में विनिरिट शक्तियों वाली वाक्यता कुर्यातों का निर्वहन करेंगे।

सारणी

क्रम सं.	प्रधिकारी का नाम	प्रधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	श्री एम.एस. कंवल, केन्द्रीय उत्पादन गुटक कलक्टर सक्रम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय इलाहाबाद होगा।	स्वापक शौषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिरिट सभी व्यक्ति जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण व्यूरो, वाराणसी के क्षेत्रीय एकक की प्रधिकारिता के अन्तर्गत प्रबंध रूप से अंजित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितबद्ध हैं।
2.	श्री क. वी. वैथनाथन, सीमाशुल्क कलक्टर (निवारक), सक्रम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय मुम्बई होगा।	स्वापक शौषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिरिट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण व्यूरो मुम्बई के क्षेत्रीय एकक की प्रधिकारिता के अन्तर्गत प्रबंध रूप से अंजित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितबद्ध हैं।
3.	श्री ही. के. प्रावाय, सीमाशुल्क कलक्टर (निवारक) सक्रम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय कलकत्ता होगा।	स्वापक शौषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिरिट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण व्यूरो, कलकत्ता के क्षेत्रीय एकक की प्रधिकारिता के अन्तर्गत प्रबंध रूप से अंजित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितबद्ध हैं।
4.	श्री ए.के. पाण्डे, सीमाशुल्क कलक्टर सक्रम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय नई विल्ली होगा।	स्वापक शौषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिरिट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण व्यूरो, विल्ली के क्षेत्रीय एकक की प्रधिकारिता के अन्तर्गत प्रबंध रूप से अंजित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितबद्ध हैं।
5.	श्री ए.ए. गोविन्दगत, सीमाशुल्क कलक्टर, सक्रम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय मद्रास होगा।	स्वापक शौषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68क की उपधारा (2) में विनिरिट सभी व्यक्ति, जो स्वापक पदार्थ नियंत्रण व्यूरो, मद्रास के क्षेत्रीय एकक की प्रधिकारिता के अन्तर्गत प्रबंध रूप से अंजित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हितबद्ध हैं।

S.O. 383(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 68G of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby appoints the officers specified in column 2 of the Table below (being officers not below the rank of Joint Secretary to the Government), to perform the functions of the Administrator under the said Act and direct that the said Administrator perform the functions in respect of the persons specified in the corresponding entries in column 3 thereof.

TABLE

Sl. No.	Name of Officers	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Shri M. S. Kanwal, Collector of central Excise, Administrator with Headquarters at Alhabad.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the zonal unit of Narcotics Control Bureau, Varanasi.
2.	Shri K.V. Vaidyanathan, Collector of Customs (Preventive) Administrator with Headquarters at Bombay.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the zonal unit of Narcotics Control Bureau, Bombay.

1	2	3
3.	Shri D.K. Acharya, Collector of Customs (Preventive) Administrator with Headquarters at Calcutta.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the Zonal Unit of Narcotics Control Bureau, Calcutta.
4.	Shri A.K. Pande, Collector of Customs Administrator with Headquarters at New Delhi	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the zonal unit of Narcotic Control Bureau, Delhi
5.	Shri S.A. Govind-Raj, Collector of Customs Administrator with Headquarters at Madras.	All persons specified in sub-section (2) of section 68A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 who ordinarily reside in, or who have interest in the illegally acquired property within the jurisdiction of the zonal unit of Narcotics Control Bureau, Madras.

[No. 6/89-F.No. 664/23/89-Opium]

अधिक रूप से अर्जित संपत्ति (प्राप्ति, प्रबंध और व्यय)

लियम, 1989

का.आ. 384(अ) — केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपक शोषण और मन: प्रभावी पदार्थ भ्रष्टाचार विषय, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 द्वारा

प्रदत्त प्राप्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनायी हैं,
अधिकारी:-

अध्याय- 1

प्राप्तियाँ,

1. संधित नाम और आरम्भ। (1) इन नियमों का महिना नाम अवधि रूप से अंजित संपत्ति (प्राप्ति, प्रबन्ध और व्यवस्था) नियम, 1989 है।

(2) ये शासक में प्रकाशन की सारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न होः—

(क) "आधिनियम" से स्वापक और अधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) अधिनियम है;

(ख) "प्रशासक" से अधिनियम की धारा 68च की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अधिनियम है;

(ग) "प्रवृत्त" से इन नियमों से उपायकार प्रस्तुप अधिनियम है;

(घ) "निधि" से अधिनियम की धारा 7क की उपधारा (1) के अधीन गठित आंशिक दुरुपयोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि अधिनियम है;

(ङ) "गोदाम" से अधिनियम की धारा 68च की उपधारा (2) के अधीन प्राप्त संपत्ति के भंडार करण के लिए गोदाम अधिनियम है;

अध्याय- 2

प्रशासकों को सहायता

3. प्रशासकों को सहायता:-—केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर कर्म-वारीबृन्द के ऐसे सदस्यों और अन्य अधिकारीयों की, जिन्हें वह उचित समझे, इन नियमों के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और कर्मचारों का निवन्द्व भरने में प्रशासक की सहायता करने के लिए उपचारा कर भकेगी।

अध्याय- 3

गोदामों का नामनिवेशन, संपत्ति की प्राप्ति और प्रबन्ध

4. गोदामों का नामनिवेशन :-—(1) प्रशासक अधिनियम की धारा 68च की उपधारा (1) या धारा 68म की उपधारा (3) के अधीन किए गए आदेशों में किया गया अधिनियम के भंडारकरण के लिए उनमें गोदामों का व्यवहार करने के लिए गोदामों को भारी अधिनियम कर दिया जाएगा।

(2) प्रशासक परिवर्त की सुरक्षा, भंडारकरण धमता, संपत्ति की प्रकृति और अन्य सुरक्षा आदेशों को ध्यान में रखते हुए उपनियम (1) में निर्दिष्ट गोदामों का व्यवहार करें।

(3) प्रत्येक नामांकित गोदाम में प्रशासक की सहायता करने के लिए एक गोदाम कीपर और एक गोदाम का भार साधक होगा।

5. संपत्तियों का समुचित विभाग:-—प्रशासक संपत्तियों प्राप्त करने के तरम्य, उक्त अधिनियम की धारा 68च की उपधारा (1) या धारा 68म की उपधारा (3) जैसी भी स्थिति हो, के अधीन किए गए आदेश में वर्णित विभिन्नियों के प्रति निर्देश द्वारा ऐसी संपत्ति की पहचान सुनिश्चित करें।

6. गोदाम रजिस्टर:-—प्रशासक नियम 7 में निर्दिष्ट संपत्तियों में भिन्न संपत्ति भी वाचत विभिन्नियों अधिनियम करने के लिए प्रस्तुप 1 में रजिस्टर रखवाएगा।

7. मूलवान वस्तुओं के लिए रजिस्टर ---संपत्ति, प्रथम् सोना और मोते के आधिकारण, हीरे (जिनके अन्तर्गत रक्षा और बिना कटे हीरे भी हैं), दीर्घों से शिल वस्तुओं और कम मूल्य वाले वस्तुओं और हाथ की धड़ियों (जिनमें इसके पश्चात् "भूत्यवान वस्तुएँ" कहा गया है) की वाचत विभिन्नियों अधिनियम करने के लिए प्राप्तुप 2 में एक रजिस्टर रजिस्टर रखवाएगा।

8. संपत्ति का भंडारकरण ---(1) प्रशासक यह सुनिश्चित करेगा कि उन पैकेजों को जिनमें मूलवान वस्तुएँ हैं गोदाम में एक लोहे की अलमारी और बालू में डबल लाली गोदाम के अधीन रखा जाए। जिसकी एक छाँव गोदाम कीपर के पास रहे और दूसरी छाँवी गोदाम भार साधक के।

(2) जहाँ किसी विधिमान्य कारण से इन नियमों पर पहुंचा जाए कि उन पैकेजों को जिनमें मूलवान वस्तुएँ हैं, गोदाम में नहीं रखी जा सकती तो ऐसे पैकेजों को भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की विरासी शाखा में भन्न रूप से इन प्रयोजन के लिए अधिभास लाकर्फर्म में रखा जाएगा।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट पैकेजों का आधारानुसार, आमानुसार, वरानीसार और पुनः जांच और निरीक्षण को सुकर बनाने के लिए समुचित पहचान विद्यों सहित, अवस्थित रूप भंडारकरण किया जाएगा।

9. भूमि या भवन का प्रबन्ध ---प्रशासक अधिनियम की धारा 68न में नियष्ट किसी भी अधिकारी को ऐसी रिक्त भूमि या भवन का कड़ा लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जिसकी बाबत ---

(i) अधिनियम की धारा 68च की उपधारा (1) के अधीन ऐसी भूमि या भवन को अधिकृत करने या रोक लेने का अवैध किया गया है, या

(ii) ऐसी भूमि या भवन के समान्तरण के लिए अधिनियम की धारा 80म की उपधारा (1) के अधीन आदेश किया जा चुका है।

10. भूमि या भवन का संधिभोग ---(1) जहाँ भूमि या भवन की प्रकृति वाली भी और संपत्ति किसी पट्टेदार या किरायेदार के कड़े में हो और ऐसी संपत्ति के विशेष अधिनियम की धारा 68च की उपधारा (1) के अधीन भी आदेश किया गया हो तो प्रशासक पट्टेदार या किरायेदार को ऐसे निवासियों और शर्तों के अनुसार, जो अधिनियम की धारा 68 च की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने की तारीख को विश्वान भी, ऐसी भूमि या भवन को अपने अधिभोग में भगाए रखने की अनुमति दे दियेगा।

(2) ऐसी संपत्ति से प्राप्त प्राप्त को तब तक प्रशासक के पास रखा जाएगा जब तक कि सभी प्राधिकारी धारा 68च की उपधारा (3) के अधीन उसे समरप्त संपत्ति घोषित नहीं कर देता है।

(3) जहाँ किसी संपत्ति की वाचत यह विवरण कर दी जाए कि वह अधिनियम के अधीन समरप्त ही जा सकती वहाँ प्रशासक युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसी संपत्ति और उससे प्राप्त प्राप्त, उसमें ऐसे अद्य, यदि कोई हो, जो सांति के अनुरक्षण और प्रबन्ध के संबंध में उपगत किए गए थे, काटने के पश्चात् उस व्यक्ति को लौटा दिया।

11. भूमि या भवन का अधिलेख ---प्रशासक प्रस्तुप 3 में भूमि या भवन का अधिलेख रखेगा।

12. मूलवान वस्तुओं से भिन्न संपत्ति का भंडारकरण ---(1) मूलवान वस्तुओं से भिन्न जंगल गंगन को अलपारियों और रेसों में रखा जाएगा।

(2) प्रचेक सलमारी और ऐक का एक स्टाक कार्ड होगा जिसमें मामला रहे, और संपत्ति का पूर्ण विवरण उपलब्धित होगा।

स्टाक कार्ड का स्थान :—गोदाम का भार साधक यह सूनिश्चित करेगा कि ऐकों या अलमारियों या संपत्ति के भेदारकरण के लिए प्रयुक्त किसी अन्य वस्तु में ऐसे स्टाक कार्ड प्रविधित किए जाएं जिनमें मामला में, और भेदारकरण संपत्ति का पूर्ण विवरण उपलब्धित हो।

14. पैकेजों वा खोलना और उन्हें फिर से मुहूर बंद करना :—(1) यदि किसी पैकेज को किसी बारण से ओला जाता है तो ऐसा प्रशासन का आवेदन प्रसिद्ध प्राप्त करने के पश्चात् स्थामी और सबद्ध गोदाम भार साधक की उपस्थिति में किया जाएगा।

(2) पैकेजों वो यह उद्देश्य पूरा होने के तुरन्त पश्चात् जिसके लिए ऐसे पैकेजों को ओला गया था, स्थामी और सबद्ध गोदाम भार साधक की उपस्थिति में किया जाएगा।

(3) फिर में सदूरबंद करने के पश्चात् स्थामी और सबद्ध गोदाम भार साधक अपली-अपली मृदूर लाना।

15. अधिग्रहीत अविहृत बाहनों का अनुरक्षण :—बाहनों जैसे बायु-याम, जलयान मोटरयाम और किसी प्राप्त बाहन की गोदाम भार साधक समुचित रूप से अनुरक्षा करेगा।

प्रधानाय-4

संपत्ति का व्यय

16. प्रयुक्ति, विनियोग वस्तुओं, आदि का व्यय :—अधिनियम की धारा 7क के अधीन निधि में विकल्प आगम जमा करने की शर्त के अधीन रहते हुए, प्रशासक की विनियोग वस्तुओं का सिन्हलिंगित ढंग से व्यय करेगा, अर्थात् :

17. मूल्यवाल वस्तुओं का व्यय :—अधिनियम की धारा 7क के अधीन निधि में विकल्प आगम जमा करने की शर्त के अधीन रहते हुए, प्रशासक की विनियोग वस्तुओं का सिन्हलिंगित ढंग से व्यय करेगा, अर्थात् :

(1) सोना, सोने के आभूषण, नींदी और चाँदी के आभूषण :—भूल्य-बाम वस्तुओं, अर्थात् सोना, सोने के आभूषण, चाँदी और चाँदी के आभूषण, भारत सरकार के टकसाल में जमा किए जाएंगे, जो ऐसी संपत्ति का मूल्य केवलीय सरकार के नाम में जमा करेंगी।

(2) हीरे :—रफ और बिना कटे हीरे के आगम अनुज्ञित शारियों को उनकी अनुज्ञियों के प्रति विकलित करके नीलामी या निविदा द्वारा बेचा जाएगा। कटे हुए हीरे और पालिश विए गए हीरों को नीलामी या निविदा द्वारा इस विनियोगित शर्त पर बेचा जाएगा कि ऐसे हीरों का नियन्त्रित किया जाएगा।

(3) हीरों से भिन्न वस्तुओं और कम कीमत वाले रत्नों को देशी बाजार में अनुज्ञित शारियों द्वारा उनकी अनुज्ञियों के प्रति विकलित करके नीलामी या निविदा द्वारा बेचा जाएगा।

(ii) हीरों से भिन्न वाले रत्नों को देशी बाजार में अनुज्ञित शारियों द्वारा उनकी अनुज्ञियों के प्रति विकलित करके नीलामी या निविदा द्वारा बेचा जाएगा।

18. कर्मसी का व्यय :—(1) आर्थिक और विदेशी कर्मसी को भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राज्यीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा।

(2) इस प्रकार जमा की गई रकम को इस प्रथितियम के अधीन गठित निधि के नाम में जमा किया जाएगा।

19. अन्य संपत्ति का व्यय :—नियम 16 से 18 तक में उल्लिखित संपत्तियों से भिन्न संपत्ति का व्यय नार्थनिक नीलामी द्वारा किया जाएगा।

20. भूमि या भवन का व्यय :—म्यावर मैनेजिंग के अंतर्गत या व्ययन से संवित्रित विशेष के नुसंहत उआवत्तों के अंतर्गत रहते हुए और अधिनियम की धारा 7क के अंतर्गत विधि में विकल्प आगम जमा करने की शर्त के अंतर्गत रहते हुए भूमि या भवन का निविदा या वर्गविक नीलामी द्वारा व्ययन किया जाएगा।

21. बाहनों का व्यय :—बाहनों जैसे बायुयान, जलयान और अन्य प्रकार के बाहनों को सार्वजनिक नीलामी या निविदा द्वारा बेचा जाएगा।

22. रिपोर्ट और विकल्पीय प्रमुख वर्गना :—प्रशासक अधिकारी नियंत्रण व्यवस्था को एक हीमासिक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें उस संपत्ति का मूल्य जो, प्राप्त की गई है और जिसका व्ययन किया गया है और गोदामों तथा बैंकों में रखी गई सभी संपत्तियों का अंतिम प्रतिशेष उपलब्धित होगा।

प्रधानाय-5

प्रक्रीय

23. कानूनिक रिपोर्ट :—गोदाम भार साधक प्रत्येक मास में प्रशासन को उस संपत्ति की, जो उस अवधि के दौरान प्राप्त हुई हो, या जिसका व्ययन किया गया हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

24. कानूनिक नियोजन :—प्रशासक गोदाम में रखी गई सभी संपत्ति की सुरक्षा समुचित लेखा और प्रबन्ध सूनिश्चित करने के लिए ऐसे अधिकारियों की सहायता में, जो वह उत्तिष्ठ समझे, अनिवार्य नियोजन और सत्यावान करेगा।

25. प्राप्ति और व्ययन का अभियोग :—प्रशासक उन सभी संपत्तियों की जिन्हें इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त किया गया है या जिनका व्ययन किया गया है, प्राप्ति और व्ययन का अभियोग रखेगा। वह प्राप्ति सभी आय और ऐसी संपत्ति को प्राप्ति प्रबन्ध और व्ययन पर उपरान अवय को लेखा भी रखेगा।

प्रलम्प 1

(नियम 6 देखिए)

गोदाम रजिस्टर

1. गोदाम प्रविलिंग त्रैम सं.
2. स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अपराध सं.
3. मुहरखंड पैकेजों/प्राधानों में संपत्ति का विवरण
4. पैकेजों/प्राधानों की सं.
5. माला (पैकेज/आधानानुसार)
6. अभियुक्त का नाम और पता
7. अभिग्रहण/जमा करने वाले अधिकारी का नाम उसके सरकारी पदनाम और पते सहित।
8. अभिग्रहण/जमा करने वाले अधिकारी द्वारा पैकेजों/प्राधानों पर लगाई गई मुद्रक का प्रतिक्रिय।
9. जमा करने की तारीख और समय
10. सभी प्राधिकारी/द्वायब्यूनल को दिखाने के लिए बाहर से जाने और फिर से आपस लाने की प्रविष्टियाँ।
11. व्ययन के लिए ले जाए जाने की तारीख और समय
12. व्ययन की प्रविष्टियाँ
13. व्ययन प्रमाणपत्र, जिसके अन्तर्गत कीमत संदाय विशिष्टियाँ और निधि के नाम में जमा रकम भी है।
14. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियाँ।

प्रलम्प 2

(नियम 7 देखिए)

मूल्यवान बस्तुओं के लिए गोदाम रजिस्टर

1. गोदाम प्रविलिंग त्रैम सं.
2. स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अपराध सं.
3. मुहरखंड पैकेजों/प्राधानों में संपत्ति का विवरण।
4. पैकेजों/प्राधानों की सं. (मदातुसार)
5. प्रविलिंग के समय मुहर की दशा
6. माला (पैकेज/आधानानुसार)
7. अभियुक्त का नाम और पता
8. अभिग्रहण/जमा करने वाले अधिकारी का नाम उसके सरकारी पदनाम और पते सहित।
9. अभिग्रहण/जमा करने वाले अधिकारी द्वारा पैकेजों/प्राधानों पर लगाई गई मुद्रक का प्रतिक्रिय।
10. जमा करने की तारीख और समय
11. सभी प्राधिकारी/द्वायब्यूनल को दिखाने के लिए बाहर से जाने और फिर से आपस लाने की प्रविष्टियाँ।
12. व्ययन के लिए ले जाए जाने की तारीख और समय
13. व्ययन की प्रविष्टियाँ।
14. व्ययन का प्रमाणपत्र, जिसके प्रत्यर्गत कीमत संदाय विशिष्टियाँ और औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए शास्त्रीय निधि में जमा की गई रकम भी है।
15. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियाँ।

* मूल्यवान बस्तुओं के अन्तर्गत ये आएँगे:—(1) बहुमल्य और कम कीमत वाले रत्न; (2) सोना और सोने की बस्तुएँ; (3) आभूषण; (4) चांदी और चांदी की बस्तुएँ; और (5) अश्वियाँ।

प्रश्न 3

(नियम 11 देखिए)

भूमि और भवन के लिए अधिकार

क्रम सं.	प्राप्तराधी सं.	अंतिम स्वामी की विशिष्टियाँ	अवस्था	नगर पालिका राजस्व अधिकार के मानुसार विवरण	दोनों (भूमि की वसा में)	मूल्य	वाधिक आय	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[सं. 7/89-का.सं. 664/23/89—प्रक्रीम]

THE ILLEGALLY ACQUIRED PROPERTY (RECEIPT, MANAGEMENT AND DISPOSAL) RULES, 1989

S.O. No. 384(E).—In exercise of the powers conferred by section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

CHAPTER—I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Illegally Acquired Property (Receipt, Management and Disposal) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);

(b) “Administrator” means any officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 68G of the Act;

(c) “Form” means form annexed to these rules;

(d) “Fund” means the National Fund for Control of Drug Abuse, constituted under sub-section (1) of section 7A of the Act;

(e) “Godown” means a godown for storage of property received under sub-section(2) of section 68G of the Act.

CHAPTER—II

ASSISTANCE TO THE ADMINISTRATORS

3. Assistance to the Administrators.—The Central Government may provide from time to time such members of staff and other persons as it thinks fit to assist the Administrator in exercise of his powers and performance of duties under these rules.

CHAPTER—III

DESIGNATION OF GODOWNS, RECEIPT AND MANAGEMENT OF PROPERTY

4. Designation of godowns.—(1) The Administrator shall designate as many godowns as may be necessary for the storage of property mentioned in the orders made under sub-section (1) of section 68F or sub-section (3) of section 68I of the Act.

(2) The Administrator shall select godowns referred to in sub-rule(1), keeping in view the security of the premises, storage capacity, nature of property and other relevant factors.

(3) Each designated godown shall have a godown keeper and a godown-in-charge to assist the Administrator.

5. Proper accounting of properties.—The Administrator shall, at the time of receiving the properties, ensure proper identification of such property with reference to its particulars mentioned in the order made under sub-section (1) of section 68F or sub-section (3) of section 68I of the Act, as the case may be.

6. Godown register.—The Administrator shall cause a register in Form I for recording entries in respect of property other than the properties referred to in rule 7 to be maintained.

7. Godown register for valuables.—The Administrator shall cause a register in Form II for recording entries in respect of property, namely, gold and gold jewellery, diamonds (including rough and uncut diamonds), precious and semi-precious stones other than diamonds and wrist watches (hereinafter called ‘valuables’) to be maintained.

8. Storage of property.—(1) The Administrator shall ensure that the packages containing valuables are kept in the godown in an iron safe and vault, under double lock system one key remaining with the godown-keeper and the other to be retained by the godown-incharge.

(2) Where, for any valid reasons, it is found that the packages containing valuables may not be kept in godown, such packages shall be kept in lockers obtained exclusively for this purpose, either with any branch of the Reserve Bank of India or of any nationalised bank.

(3) The packages referred to in sub-rule(1) and (2) shall be stored systematically case-wise, serial-wise, year-wise and with proper identification marks to facilitate re-check and inspection.

9. Management of Land and Building.—The Administrator may authorise any officer referred to in section 68 T of the Act to take possession of vacant land or building in respect of which—

- (i) an order of seizure of freezing of such land or building has been made under sub-section (1) of section 68F of the Act; or
- (ii) an order for forfeiture of such land or building has been made under sub-section (1) of section 80I of the Act.

10. Occupation of land or building.—(1) Where any property in the nature of land or building is in possession of a lessee or a tenant and against such property an order under sub-section(1) of section 68F of the Act has been made, the Administrator may allow the lease or tenant to continue in occupation of such land or building in accordance with such terms and conditions which existed on the date of passing an order under sub-section(1) of section 68F of the Act.

(2) The income derived from such property shall be kept with the Administrator until such

time the competent authority declares the property forfeited under sub-section (3) of section 681.

(3) Where any property is declared not liable to be forfeited under the Act, the Administrator shall, within reasonable time, return to the person such property and the income derived therefrom after deducting such expenses if any, which were incurred on the maintenance and management of the property.

11. Record of land or building.—The Administrator shall maintain a record of land or building in Form III.

12. Storage of property other than valuables.—(1) movable property other than valuables shall be stored in Almirahs and racks.

(2) Each Almirahs and rack shall have a stockcard indicating the case No. and full description of the property.

13. Placement of Stock-cards.—The godown-in-charge shall ensure that the racks or almirahs or any other thing used for storage of property, display stock-cards indicating the case No. and full description of the property stored.

14. Opening and re-sealing of the packages.—(1) Where any package is to be opened for any reason, the same shall be opened in the presence of the owner and the concerned godown-in-charge after obtaining the order of the Administrator.

(2) The packages shall be resealed immediately after the purpose, for which such packages were opened, is fulfilled in the presence of the owner and the concerned godown-in-charge.

(3) At the time of resealing, the owner, and the concerned godown-in-charge, shall affix their seals.

15. Maintenance of seized/confiscated conveyances.—Conveyances, such as aircrafts, vessels, motor vehicles and any other mode of conveyance shall be properly maintained by the godown-in-charge.

CHAPTER—IV

DISPOSAL OF PROPERTY

16. Disposal of livestocks, perishables, etc.—Subject to the sale proceeds being credited to the Fund under section 7A of the Act, the Administrator shall dispose of the livestock and property which is perishable in nature or prone to decay in the manner as he deems fit.

17. Disposal of valuables.—Subject to the sale proceeds being credited to the Fund under section 7A of the Act, the Administrator shall dispose of the valuables mentioned below in the following manners, namely :—

- (1) Gold, Gold Jewellery, Silver and Silver Jewellery : The valuables, namely, gold, gold jewellery, silver and silver jewellery shall be deposited in the Government of India Mints which shall credit the value of such property to the Central Government.
- (2) Diamonds : Rough and uncut diamonds shall be sold either by auction or tender to import licence holders against debit of their licences. Cut and polished diamonds shall be sold by auction or tender with the specific condition that such diamonds shall be exported.
- (3) Precious and semi-precious stones other than diamonds : (i) Rough and uncut precious and semiprecious stones other than diamonds shall be sold by auction or tender to holders of import licences against debit of their licencees, in the internal market.
(ii) Cut and polished precious and semi-precious stones, other than diamonds, shall be sold internally, by auction or by tender.

18. Disposal of currency.—(1) Indian and Foreign currency shall be deposited with the Reserve Bank of India or any nationalised Bank.

(2) The amount so deposited shall be credited to the Fund constituted under this Act.

19. Disposal of other property.—Property other than those mentioned in rules 16 to 18 shall be disposed of by public auction.

20. Disposal of land or building.—Subject to the relevant provisions of any law relating to the acquisition or disposal of immovable property and also subject to the sale proceeds being credited to the Fund under section 7A of the Act, land or building shall be disposed of by tender or by public auction.

21. Disposal of conveyances.—Conveyances, such as aircrafts, vessels, vehicles and other mode conveyance shall be sold by public auction or by tender.

22. Furnishing Reports and Returns.—The Administrator shall furnish a quarterly statement to the Narcotics Control Bureau indicating the value of the property received and disposed of and the closing balance of all properties kept in the godowns and banks.

CHAPTER—V MISCELLANEOUS

23. Periodical Reports.—The godown-in-charge shall submit, every months, a report to the Administrator of the property received or disposed of during that period.

24. Periodical Inspection.—The Administrator with a view to ensuring safety, security, proper accounting and management of all properties in the godowns, conduct physical inspection and verification with the help of such officers as he thinks fit.

25. Record of Receipt and Disposal. The Administrator shall maintain a record of receipt and disposal of all properties received and disposed of under these rules. He shall also maintain an account of all income received and expenditure incurred on receipt, management and disposal of such property.

FORM I

(See rule 6)

GODOWN REGISTER

1. Godown entry S. No.
 2. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Crime No.
 3. Description of property in the sealed packages/containers.
 4. No. of packages/containers
 5. Quantity (package/containerwise).
 6. Name(s) and address(es) of accused.
 7. Name with official designation and address of seizing/depositing officer.
 8. Facsimile of the seal put on the packages/containers by the seizing officer/depositing officer.
 9. Date and time of deposit.
 10. Particulars of exit and re-entry for exhibiting to competent authority/Tribunal.
 11. Date and time of removal for disposal.
 12. Disposal particulars.
 13. Certificate of disposal including price payment particulars and credit to the Fund.
 14. Remarks of the Inspecting Officer(s)
-

FORM II

(See Rule 7)

GODOWN REGISTER FOR VALUABLE*

1. Godown entry S. No.
2. Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Crime No.
3. Description of the valuables in packages/containers.
4. No of packages/containers (item-wise).
5. Condition of seal at the time of entry.
6. Quantity (package/container-wise).
7. Name(s) and address(es) of accused.
8. Name with official designation and address of sizing/depositing officer.
9. Facsimile of the seal put on the packages/containers by the seizing/depositing officer.
10. Date and time of depsoit.
11. Particulars of exit and re-entry for exhibiting to Competent Authority/Tribunal.
12. Date and time of removal for disposal.
13. Disposal particulars.
14. Certificate of disposal including price payment particulars and credit to the National Fund for Control of Drugs Abuse.
15. Remarks of the Inspecting Officer(s)

(*Valuables will include : (1) Precious and semi-precious stones ; (2) Gold and articles of gold ; (3) Jewellery ; (4) Silver and articles of silver ; and (5) Watches.

FORM III
(See Rule 11)
RECORD FOR LAND AND BUILDING

S. Crime No.	Particulars of the last owner(s)	Location	Description as per Municipal revenue records	Area (in case of land)	Value	Annual income	Remarks	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

[No. 7/89-F.No. 664/23/89-OPIUM]

का. ग्रा. 385(अ) :—जौनीय सरकार, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) को धारा 68ट के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 68ब, धारा 68ज, धारा 68ट की उपधारा (1) या 68ट के घटीन किए गए आवेदों के विवर अपीलों की सुनवाई करने के लिए समप्रहृत संपत्ति के लिए अपील द्राघब्युनल गठित करती है और निम्नलिखित की नियम: अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है,—

- (1) ग्यायनूति थी गी. आर. खासा (सेवानिवृत्त ग्यायनूति, विली उच्च आदालत) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक संपत्ति समवहरण) अधिनियम, 1976 के अधीन गठित समझूत संपत्ति के लिए अपील द्राघब्युनल का अध्यक्ष
- (2) श्री पी. आर. राव, तस्करी और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समवहरण) अधिनियम, 1976 के अधीन गठित समझूत संपत्ति के लिए अपील द्राघब्युनल का सदस्य
- (3) श्री जी. आर. पटवर्धन, तस्करी और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समवहरण) अधिनियम, 1976 के अधीन गठित समझूत संपत्ति के लिए अपील द्राघब्युनल का सदस्य।

[सं. 8/89--फा. न. 664/23/89-ओपियम]

S.O. No. 385(E) —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 68N of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby constitutes an Appellate Tribunal for Forfeited Property for hearing appeals against orders made under section 68F, section 68I, sub-section (1) of section 68K section 68L, and appoints the following

as Chairman and Members respectively of the said Tribunal,—

- (1) Mr. Justice D.R. Khanna (Retired Judge of the Delhi High Court), Chairman of the Appellate Tribunal for Forfeited Property constituted under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976. Chairman.
- (2) Shri P.R. Rao, Member of the Appellate Tribunal for Forfeited Property constituted under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 Member.
- (3) Shri G.R. Patwardhan, Member of the Appellate Tribunal for Forfeited Property constituted under the Sumugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976. Member.

[No. 8/89-F.No. 664/23/89 Opium]

का. ग्रा. 386(अ) :—जौनीय सरकार, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) को धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 68ट के अधीन गठित समप्रहृत संपत्ति के लिए अपील द्राघब्युनल के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों के लिए उपबंध करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समझूत संपत्ति के लिए अपील द्राघब्युनल (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों में) 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होगे।

2. परिमाणानुसार : इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अनेकित न हो :—

(क) "भवित्वित्यम्" से स्वाधेन औषधि और मन : प्रमाणी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 2) द्वारा यथा संशोधित स्वाधेन औषधि और मन, प्रमाणी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) अनिप्रेत है;

(ख) "इच्छा" से अधिनियम की धारा 65उ की उपलब्ध (1) के अधीन गठित ग्रील द्राघिमूली अनिप्रेत है;

(ग) "न्यायालय" के बंदर्पंत मुख्य न्यायालयी, कार्यकारी न्यायालयी अधिसिक्त न्यायालयी, कार्यकारी न्यायालयी भी है।

(द) "सदस्य" से द्राघिमूली का सदस्य अनिप्रेत है।

3. अध्यक्ष को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, भत्ते आदि:

(1) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई न्यायालयी, जिसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया हो, उच्च शर्ट पर मासिक बेतन प्राप्त करने का हक्कार होगा जो उसे, यासिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायालयी के रूप में प्राप्त है। वह ऐसे भत्तों और अन्य फायदों का भी हक्कार होगा जो, यासिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायालयी को ग्राह्य है।

(2) जहाँ अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में अर्द्धा बार्वेन के दोहरा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायालयी के रूप में सेवानिवृत्ति हो जाता है या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्ति न्यायालयी को इस हेसियत में नियुक्त किया जाता है तो उसे उस अवधि के लिए, जिसमें वह अध्यक्ष के रूप में सेवारत रहता है, ऐसा बेतन, जो उसकी वेशन और किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के वेशन समतुल्य मिला कर अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके द्वारा लिए गए अंतिम बेतन में अधिक नहीं होगा, दिया जाएगा वह ऐसे भत्तों और फायदों के भी हक्कार होगा जो, यासिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायालयी को ग्राह्य है।

(3) ऐसे अधिकारी को, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्ति न्यायालयी नहीं है और जिसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, 8,000/- प्रतिमास बेतन दिया जाएगा और वह ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हक्कार होगा जो समतुल्य बेतन पाने वाले सरकारी अधिकारी को ग्राह्य है।

परंतु यदि अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के समय ऐसा अधिकारी सरकारी या किसी स्थानीय निकाय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन प्राधिकरण के अधीन अपनी पूर्व सेवा की बाबत कोई वेशन प्राप्त नहीं है तो ऐसे बेतन में से वेशन और किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के वेशन समतुल्य की रकम घटा दी जाएगी।

4. सदस्यों का विद्या जाने वाले पारिश्रमिक, भत्ते आदि : सदस्य के हरे में नियबल अधिकत की 7,600/- प्रतिमास बेतन दिया जाएगा और वह ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हक्कार होगा जो समतुल्य बेतन पाने वाले एवं सरकारी अधिकारी को ग्राह्य है :

परंतु यदि सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के अधिकारी सरकारी या किसी स्थानीय निकाय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन प्राधिकरण के अधीन अपनी पूर्व सेवा की बाबत कोई वेशन प्राप्त नहीं है तो ऐसे बेतन में से वेशन और किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के वेशन समतुल्य की रकम घटा दी जाएगी।

5. सदस्यों के कार्यकारी के दोगने मेवानिवृत्ति : जहाँ कोई नहीं, सदस्य के रूप में कार्यकारी के दोगने सरकारी या किसी स्थानीय निकाय।

मंत्रालय के स्वामित्व में या सेवानिवृत्ति हो जाए है तो उसे उस अवधि के बेतन से, जिसके दौरान वह ऐसी सेवानिवृत्ति के पश्चात् सदस्य के रूप में सेवा करता है, वेशन और अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के वेशन समतुल्य की रकम घटा दी जाएगी।

6. याकां भत्ता : (1) (i) यदि प्रज्ञन उच्चतम न्यायालय या हिसों उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायालयी है तो वह द्राघिमूल के कार्य के संबंध में अपने द्वारा की गई याकां की बाबत उन्हीं दरों पर याकां भत्ता पाने का हक्कार होगा जो, यासिति, उच्चतम न्यायालय न्यायालयी (याकां भत्ता) नियम, 1959 वा न्यायालय न्यायालयी (याकां भत्ता) नियम, 1956 के अधीन उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायालयी को ग्राह्य है।

(ii) यदि प्रज्ञन उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायालयी है तो वह द्राघिमूल के कार्य के संबंध में अपने द्वारा की गई याकां की बाबत उन्होंने पुनः नियोजन के समर प्रवृत्त दरों पर अपनी हक्कारी के अनुसार याकां भत्ता यादेनिक भत्ता पाने का सक्षम होगा :

परंतु उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायालयी में दूर स्थानों में अपने सामान्य कूटों से विश्व कूटों का निर्वहन करने के लिए, यासिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायालयी को ग्राह्य उच्चतम दैनिक भत्ते के कारबों का हक्कार नहीं होगा :

(2) वह अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायालयी या सेवानिवृत्त न्यायालयी नहीं है या कोई सदस्य द्राघिमूल के कार्य के संबंध में धारने द्वारा की जाने वाली याकां की बाबत उन्हीं दरों पर याकां भत्ता प्राप्त करने का हक्कार होगा जो समतुल्य बेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को ग्राह्य है।

7. छुट्टी : (1) जहाँ अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायालयी हो वह ऐसी छुट्टी का हक्कार होगा जो उसे यासिति, उच्चतम न्यायालय न्यायालयी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायालयी (सेवा शर्ते) अधिनियम 1954 (1954 का 28) के अधीन उसे ग्राह्य है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायालयी, जो अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति होता है, वह सेवानिवृत्ति की तारीख से अन्तिम सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा ग्राह्य होगा।

(2) जहाँ अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायालयी हो वह ऐसी छुट्टी का हक्कार होगा जो केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन सरकारी अधिकारी को ग्राह्य हो।

(3) सदस्य के रूप में नियुक्त अधिकारी उस छुट्टी का हक्कार होगा जो केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1973 के अधीन सरकारी अधिकारी को ग्राह्य है :

परंतु जब किसी ऐसे अधिकारी को अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाए है जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 से, लागू वह अपनी नियुक्ति से पूर्व उसे लागू नियमों के अधीन छुट्टी के लिए पाना होगा।

8. प्रावहान : (1) जहाँ अध्यक्ष सरकार न्यायालयी हो वहाँ वही उच्चतम न्यायालय न्यायालयी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायालयी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1954 (1954 का 28), जीसी भी स्थित हो, के मनुसार प्रावहान का हक्कार होगा।

(2) ऐसा अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायालयी नहीं है और कोई सदस्य प्रावहान का हक्कार नहीं होगा।

9. व्यापारिकों : (1) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का बोर्ड द्वारा भी सेवानिवृत्त न्यायधीश, जिसे अधिकार के रूप में नियुक्त किया जाता है, कियां जो संदाय किए बिना, व्यापारिकों, उच्चतम न्यायालय न्यायधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) के अनुसार मरकारी नियाम का उच्चतम बोर्ड :

परन्तु जहाँ उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश को इस उपनियम के अनुसार नियाम की व्यवस्था नहीं ही जाती है, वहाँ उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के ऐसे रोकानिवृत्त न्यायधीश को बोर्ड के 12-1/2 प्रतिशत की दर पर मरकार कियाया भला संदेश होगा।

(2) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायधीश नहीं है, और कोई सदस्य विहित कियाएँ के संदाय पर ऐसी मरकारी बात मुविधा का हक्कदार होगा जो समतुल्य बोर्ड पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को शाहू है।

1. विकिसीय परिकर्ता (1)(i) उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायधीश, व्यापारिकों, व्यापारिकों, उच्चतम न्यायालय न्यायधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 (1958 का 41) या उच्च न्यायालय न्यायधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) के अनुसार विकिसीय परिकर्ता का हक्कदार होगा।

(ii) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायधीश, जिसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाए, ऐसी विकिसीय मुविधा जो हक्कदार होगा जो केन्द्रीय सरकार नियक्ता योजना के अधीन उपलब्ध है या जहाँ ऐसी योजना उपलब्ध मर्ही है वह ऐसी विकिसीय मुविधाओं का हक्कदार होगा जो केविंट भविमां को उपलब्ध है।

(2) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायधीश नहीं है और द्रावद्यनुल का सदस्य ऐसी विकिसीय मुविधाओं का हक्कदार होगा जो समतुल्य बोर्ड पाने वाले केन्द्रीय मरकार के अधिकारियों को शाहू है।

सेवा अधिकारी : 11. (1) (क) जहाँ उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायधीश को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वहाँ वह अध्यक्ष के रूप में अवलोकन पद तीन वर्ष तक या पैसठ वर्षों या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जैसी भी स्थिति हो और जो सी पहले हो, घासित करेगा।

परन्तु जहाँ उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीश को, व्यापारिकों, पैसठ या बासठ वर्ष की आयु के पारात् अध्यक्ष के रूप में नियुक्त या पुनः नियुक्त किया जाता है वहाँ वह अध्यक्ष के रूप में अपना पद ऐसी अवधि तक, जो तीन वर्ष से अधिक न हो, जिसका केन्द्रीय सरकार नियुक्त या पुनः नियुक्त करेगा।

(ख) जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति, जो खंड (क) के अंतर्गत मर्ही आता, अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वहाँ वह अपना पद तीन वर्ष की अवधि तक या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पूर्व हो, घासित करेगा और पुनः नियुक्त का पाल नहीं होगा।

(ग) खंड (घ) में अंतर्विट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, उसे लागू नियमों के अधीन अधिकारियों की आयु प्राप्त होने पर उस खंड में नियिट तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के पारात् एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला हो से ऐसा व्यक्ति उक्त नियमों के अधीन अपनी अधिकारियों की आयु तक अध्यक्ष के रूप में पद घासित करता रहेगा।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक पद घासित करेगा।

11. व्यापारिकों भविष्य नियम में अधिकारी : (a) अग्रणी और नदेश व्यापारिकों भविष्य नियम (केन्द्रीय सेवा) नियम 1960 के अधीन साधारण भविष्य नियम नेवा में उसी ढंग से अधिकारी बोर्ड के हक्कदार होंगे जिस छंग से अन्य केन्द्रीय मरकारी कम्बार्शी नहरते हैं।

(ब) ऐसे अध्यक्ष और सदस्य, जिन्हें मरकारी नेवा से सेवानिवृत्त होने पर पुनः नियोजित किया जाता है, ऐसी यसको के अधीन रहते हुए, जो पुनः नियोजित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लागू हो, अधिकारी भविष्य नियम (भरत), 1962 के अधीन अधिकारी भविष्य नियम नेवा में अधिकारी बनने के हक्कदार होंगे।

12. पद की शाय प्रत्येक अवधि, जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, और जो पहले से ही सरकारी सेवा में नहीं है, परम्परागत बोर्ड के किसी ऐसे अधिकारी के समक्ष जो शाय सदस्य से नियम पंक्ति का न हो, इन नियमों में संलग्न प्रस्तुत में पद की शाय नेवा और अपने हस्ताक्षर करेगा।

13. ऐसे अध्यक्ष और सदस्यों की नेवा के निवृत्तियों और शर्तों जो तस्कर और विदेशी नुद्रा छालसाधक (मंपति संपहरण) अधिनियम के अधीन गठित समाजुत्तम संस्था के लिए आपीन द्रावद्यनुल के अध्यक्ष या सदस्य किसी बोर्ड, पारिश्रमिक भूता या आय फागदों का, जिनका इन नियमों के अधीन अध्यक्ष या सदस्य बहुदार है, द्रावद्यनुल नहीं होगा, यदि अध्यक्ष या मव्य तस्कर और विदेशी मुद्रा छालसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) जिसे इसके प्रत्यागत भूमिकोंपा बाह्य गया है) के अधीन गठित समाजुत्तम संस्था के लिए आपीन द्रावद्यनुल का, व्यापारिकों आपीन अध्यक्ष या सदस्य है और ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के पद के निवृत्त फत्योपो के अधीन गठित समपहरण पत्ति के लिए आपीन द्रावद्यनुल के व्यापारिकों अध्यक्ष या सदस्य के पद के निवृत्तों के सहवित्री री होंगे।

व्याप्ति : 14. ऐसे किसी मामले की बाबत, जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आता, अध्यक्ष और सदस्य ऐसे नियमों या आवेदों द्वारा शासित होंगे जो समसुल्य बोर्ड पाने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को लागू होंगे।

निवृत्त : 15. यदि इन नियमों के निवृत्तने से संबंध में कोई प्रभाव उद्भूत होती है तो ऐसा मामला केन्द्रीय सरकार को नियिट किया जाएगा, जो उसकी बाबत विनियोग्य करेगा।

परिणिट

प्रलय

(नियम 12 देखिए)

में.....शाय लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं इस और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सज्जी शूद्रा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभूत और अवधिता अक्षुण्ण रखूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का शूद्रापूर्वक, द्वानवारी से और पक्षपाता के बिना, नियंत्रण करूंगा।

ईश्वर मेरी सहायता करे।

हस्ताक्षर :

अध्यक्ष/सदस्य

समपहुत संपत्ति के लिए आपील
द्रावद्यनुल

अधिकारी, जिसके समक्ष शाय नी गई

[सं. 9/8-एका. सं. 664/26/88-अफीम]

S.O. 386(E) :—In exercise of the powers conferred by section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to provide for terms and conditions of service of the Chairman and other Members of the Appellate Tribunal for Forfeited Property constituted under section 68N of the Act, namely:—

1. Short title and commencement : (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1989.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions : In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) “Act” means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), as amended by the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 1988 (2 of 1989),
- (b) “Chairman” means the Chairman of the Tribunal,
- (c) “Tribunal” means the Appellate Tribunal constituted under sub-section (1) of section 68N of the Act,
- (d) “Judge” includes the Chief Justice, an acting Chief Justice, an Additional Judge an acting Judge,
- (e) “Member” means a member of the Tribunal.

3. Remuneration, allowances, etc. of the Chairman: (1) A Judge of the Supreme Court or of High Court appointed as Chairman shall be entitled to a monthly salary at the same rate as is admissible to him as a Judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be. He shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a Judge of the Supreme Court or of a High Court, as the case may be.

(2) Where the Chairman retires from service as Judge of the Supreme Court or of a High Court during the term of office of such Chairman or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court is appointed as such, he shall be paid for the period he serves as Chairman, such salary, which, together with his pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits shall not exceed the last pay drawn by him before retirement. He shall be entitled to such allowances and other benefits as are admissible to a serving Judge of the Supreme Court or High Court, as the case may be.

(3) A person not being serving Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court appointed as Chairman shall be paid a salary of Rs. 8,000/- per mensem and shall be entitled to draw such allowances as are admissible to a Government officer of equivalent pay:

Provided that if such a person at the time of his appointment as Chairman is in receipt of a pension in respect of his previous service under the Government or any local body/authority owned or controlled by the Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits.

4. Remuneration, allowances, etc. of Members : A person appointed as Member shall be paid a salary of Rs. 7,600/- per mensem and shall be entitled to draw such allowances, admissible to a Government officer of equivalent pay:

Provided that if such a person, at the time of his appointment as Member is in receipt of a pension in respect of any previous service under the Government or any local body/authority owned or controlled by Government, such salary shall be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits.

5. Retirement during the term of Member : Where a Member retired from service under the Government or any local body authority owned or controlled by the Government during the term of office as such member, his salary for the period he serves as member after such retirement shall be reduced by amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits.

6. Travelling Allowances :

(I) (i) If the Chairman is a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to draw travelling allowance at the rates as are admissible to a Judge of the Supreme Court or of a High Court under the Supreme Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1959 or, as the case may be, the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956, in respect of journeys performed by him in connection with the work of the Tribunal.

(ii) If the Chairman is a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to draw travelling allowance or daily allowance according to his entitlement at the rates in force at the time of his re-employment in respect of journeys performed by him in connection with the work of the Tribunal :

Provided that the retired judge of the Supreme Court or of a High Court shall not be entitled to the

benefit of higher daily allowance admissible to a serving Judge of the Supreme Court or of the High Court, as the case may be, for performing functions outside his normal duties in localities away from his headquarters :

(2) The Chairman, not being a Judge of a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court or any Member shall be entitled to draw travelling allowance in respect of journey performed by him in connection with the work of the Tribunal at the same rates as are admissible to a Central Government officer of equivalent pay.

7. Leave : (1) Where the Chairman is a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to such leave as may be admissible to him under the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958) or as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954). The serving Judge of the Supreme Court or of a High Court retiring during the tenure of appointment as Chairman, he would be governed by Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 with effect from his date of retirement from service.

(2) Where the Chairman is a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled to such leave as is admissible to an officer of the Government under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(3) A person appointed as [a Member shall be entitled to such leave as is admissible to an officer of the Government under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 :

Provided that where a person to whom the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 are not applicable, is appointed as the Chairman or a Member, he shall be eligible for the grant of leave under the rules applicable to him before such appointment.

8. Vacation : (1) Where the Chairman is a serving Judge, he shall be entitled to vacation in accordance with the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954).

(2) The Chairman, who is not a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court and a Member shall not be entitled to vacation.

9. Accommodation : (1) A serving Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, who is appointed as Chairman, shall be entitled without payment of rent, to the use of an official residence in accordance with the Supreme

Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954) :

Provided that where a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court is not provided residence in accordance with this sub-rule, house rent allowance at the rate of 12½% of pay shall be payable to such retired Judge of the Supreme Court or of the High Court.

(2) The Chairman, who is not a serving Judge of a retired Judge of the supreme Court or of a High Court, and a Member shall be entitled to government accommodation on payment of prescribed rent as admissible to a Central Government officer or equivalent pay.

10. Medical Attendance : (1) (i) A serving Judge of the Supreme Court or a High Court shall be entitled to medical attendance in accordance with the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958 (41 of 1958), or as the case may be, the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954).

(ii) A retired Judge of the Supreme Court or of a High Court appointed as Chairman shall be entitled to medical facilities as available under the Central Government Health Scheme or where the Central Government Health Scheme is not available, he shall be entitled to medical facilities as available to Cabinet Ministers.

(2) The Chairman, who is not a serving Judge or a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court, and a Member of the Tribunal shall be entitled to medical facilities admissible to a Central Government officer of equivalent pay.

11. Tenure : (1) (a) Where a serving Judge of the Supreme Court or of a High Court is appointed as Chairman, he shall hold office as Chairman for a period of three years or till he attains the age of sixty-five years or sixty-two years, as the case may be, whichever happens earlier,

Provided that where a retired Judge of the Supreme Court or of a High Court is appointed or re-appointed as Chairman, beyond the age of sixty-five or sixty-two years, as the case may be, he shall hold office as Chairman for such period not exceeding three years, as may be determined by the Central Government at the time of appointment or re-appointment.

(b) Where a person not falling under clause (a) is appointed as Chairman, he shall hold office for a period of three years, or till he attains the age of sixty-five years, whichever happens earlier and shall not be eligible for re-appointment.

(c) Notwithstanding anything contained in clause (b) where a person appointed as Chairman is due to retire on attaining the age of superannuation under the relevant rules applicable to him within a period of one year after completion of the period of three years referred to in that clause, such person shall continue to hold office as Chairman till the date of his superannuation under the said rules.

(2) A person appointed as Member shall hold office till he attains the age of sixty years.

11-A. Contributions of General Provident Fund and Contributory Provident Fund :

(a) The Chairman and Members shall be entitled to make contributions towards General Provident Fund Account under the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 in the same manner as any other Central Government servant.

(b) Such of the Chairman and Members, as are re-employed after retirement from Government service, shall be entitled to contribute towards the Contributory Provident Fund Account under the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 subject to such conditions as are applicable to re-employed Central Government servants.

12. Oath of office: Every person, appointed as the Chairman or as a Member, not already in Government Service shall, before entering upon office, make and subscribe to an oath of office before an officer of the Central Government not below the rank of Additional Secretary in the form appended to these Rules.

Terms and Conditions of service of Chairman and Members who are Chairman and Member of the Appellate Tribunal for Forfeited Property Constituted under SALEMFOPA

13. The Chairman or a Member of the Tribunal shall not be entitled for any salary, remuneration, allowance or any other benefits to which the Chairman or Member is entitled under these rules, if the Chairman or Member is a sitting Chairman or Member, as the case may be, of the Appellate Tribunal for Forfeited Property constituted under the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976) (hereinafter referred to as SALEMFOPA) and the terms of office of such Chairman or Member shall be co-terminus with the terms of office of the Chairman or Member, as the case may be, of the Appellate Tribunal for Forfeited Property constituted under SALEMFOPA.

14. Saving: In respect of any matter not covered by these Rules, the Chairman and a Member shall be

governed by such Rules or Orders, as may be applicable to a Central Government Officer of equivalent pay.

15. Interpretation: If any question arises relating to the interpretation of these Rules, the matter shall be referred to the Central Government, who shall decide the same.

APPENDIX FORM

(See Rule 12)

I,.....do swear/solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to India and to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will carry out the duties of my office loyally, honestly and with impartiality.

So help me God.

Signature:

CHAIRMAN/MEMBER
APPELLATE TRIBUNAL FOR FORFEITED PROPERTY

Officer before whom the oath was taken

[No. 9/89—F.No. 664/23/89—Opium]

का. आ. 387(अ) :—फेन्ड्रीय सरकार, स्वापक शौषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, प्रथमः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रांगन : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सम्पूर्ण सम्बल के लिए अपील द्राघब्यूनल (फीस) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगे।

2. अपील द्राघब्यूनल के अधिकारियों और रजिस्टरार के नियमित के लिए फीस का मापदान—(1) अपील द्राघब्यूनल के अधिकारियों और रजिस्टरार के नियमित के लिए फीस का संवाद निम्नलिखित रूप से किया जाएगा, प्रथमः—

(क) नियमित के पहले घटे या उसके किसी भाग के लिए 1 रु.

(ख) नियमित के प्रत्येक अतिरिक्त घटे या उसके किसी भाग के लिए 50 पैसे

(2) उक्त नियमित के लिए फीस नकद वी जाएगी।

3. अपील द्राघब्यूनल में अधिकारियों और रजिस्टरार की प्रमाणिणी प्रतिलिपि फाँन प्राप्ति का मापदान : (1) प्राप्ति के लिए अपील फाँन प्राप्ति की किसी भाग के लिए दो रु. होगी।

(2) किसी फोटो स्टेट प्राप्ति के लिए प्रतिलिपि फीस ऐसी प्रतिलिपि के लिए अपील द्राघब्यूनल द्वारा उपरांत दराविधि द्वारा होगा।

(3) किसी प्रति को सही प्रति के लिए में अधिप्रमाणित करते के लिए दो रु. फीस दर्शक ही नकद बदल कर सी जाएगी।

(4) प्रतिलिपि एवं पहले ही नकद बदल कर सी जाएगी।

(5) जहाँ कोई पक्कार आशुलिपिक द्वारा लिखे गए साक्ष्य की तुरंत प्रति चाहता है वहाँ प्रभार्य फीस उन फीस से $2\frac{1}{2}$ गुनों होगी जो उपनियम (1) में विनियिट की गई है, ऐसे मामले में उपनियम (1) में विनियिट फीस का पचास प्रतिशत आशुलिपिक को दिया जाएगा।

(6) जहाँ कोई प्रति शाक द्वारा भेजी जाए वहाँ आवेदक से वास्तविक शाक प्रधार पहले ही नकद से लिया जाएगा।

4. व्यापूति : इस नियम की कोई भी बात किसी भी ऐसे पक्कित को किसी रजिस्टर या दस्तावेज का निरोक्षण करते या उसके प्रति अधिप्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं बनाएँगी जिसके लिए वह किसी विधि के अधीन गा शापील द्रुष्यव्यूनल के घोरेश द्वारा प्रत्यापा हुकदार नहीं है।

[म 19/89-का. सं. 664/23/89-अपील]

बी. वी. कुमार, प्रधर सचिव

S.O. 387 (E).—In exercise of the powers conferred by section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement: (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Forfeited Property (Fees) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Scale of fees for inspection of records and registers of the Appellate Tribunal: (1) The fees which shall be paid for the inspection of the records and registers of the Appellate Tribunal shall be the following, namely:—

(a) for the first hour of inspection or part thereof: 1 Rupee

(b) for every additional hour of inspection or part thereof: 50 Paise

(2) Fees for the said inspection shall be paid in cash.

3. Scale of fees for obtaining certified copies of records and registers of the Appellate Tribunal: (1) Copying fees for supply or copies shall be rupees two per page or part thereof.

(2) Copying fees for supply of photostat copies shall, however, be the actual expenses incurred by the Appellate Tribunal for such copies.

(3) A fee of two rupees shall be levied for authenticating a copy to be a true copy.

(4) Copying fees shall be recovered in advance in cash.

(5) Where a party applies for immediate delivery of a copy of evidence taken down by a Stenographer, the fee chargeable shall be $2\frac{1}{2}$ times of those specified by sub-rule (1), in such case, fifty per cent of the fees specified by sub-rule (1) shall be paid to the Stenographer.

(6) When a copy is sent by post, the applicant shall also be charged with the actual postal charges which shall be recovered in advance in cash.

4. Saving: Nothing in these rules shall enable any person to inspect or to obtain a copy of any register or document to which he is not otherwise entitled by or under any law or order of the Appellate Tribunal.

[No. 10/89—F.No. 664/23/89—Opium]

B.V. KUMAR, Addl. Secy.

